

वदिश मंत्रालय के सहायता आवंटन में नेबरहुड को प्राथमिकता

प्रलिस के लयि:

केंद्रीय बजट, वकिस सहायता, नेबरहुड फरसट नीति, चाबहार बंदरगाह, मानवीय आवश्यकताएँ, परवासन, सीमा सुरकषा, ऋण रेखा (LOC), संयुक्त सैन्य अभयास, समुद्री, भारत-म्याँमार-थाईलैंड तरपिकषीय राजमार्ग, सार्क, बमिसटेक, व्यापार बाधाएँ, सधि, तीस्ता ।

मेन्स के लयि:

भारत के पड़ोस में सुरकषा और स्थरिता में भारत की वकिस सहायता की भूमिका ।

[स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में घोषति केंद्रीय बजट 2024-25 में, [वदिश मंत्रालय \(MEA\)](#) ने रणनीतिक साझेदारों और पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रति करते हुए अपनी [वकिस सहायता योजनाओं](#) की रूपरेखा तैयार की है ।

- यह भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप **क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और स्थरिता** को बढ़ावा देने के लयि तैयार की गई है ।

देशों के बीच वकिस सहायता कैसे वतितरति की जाती है?

- वदिश मंत्रालय के व्यय का एक बड़ा हसिसा, 4,883 करोड़ रुपए, **"देशों को सहायता"** के लयि नरिधारति कयिा गया है । इसे इस प्रकार आवंटति कयिा गया है:
 - **भूटान:** इसे सबसे अधिक **2,068.56 करोड़ रुपए** की सहायता मलिी, हालाँकि यह पछिले वर्ष के **2,400 करोड़ रुपए** से थोड़ा कम है ।
 - **नेपाल:** इसे **700 करोड़ रुपए** आवंटति कयिा गए, जो पछिले वर्ष के **550 करोड़ रुपए** से अधिक है ।
 - **मालदीव:** इसने पछिले वर्ष के लयि **770.90 करोड़ रुपए** की संशोधति राशा के बावजूद **400 करोड़ रुपए** का आवंटन बनाए रखा ।
 - **श्रीलंका:** इसे **245 करोड़ रुपए** मलिे, जो पछिले वर्ष के **150 करोड़ रुपए** से अधिक है ।
 - **अफगानसितान:** अफगानसितान को **200 करोड़ रुपए** मलिे, जो मौजूदा चुनौतियों के बीच देश की स्थरिता और वकिस में सहायता करने में भारत की भूमिका को दर्शाता है ।
 - **मालदीव:** भारत वरिधी प्रदर्शनों और इसके शीर्ष नेतृत्व की टपिपणियों के बावजूद मालदीव को **400 करोड़ रुपए** मलिे ।
 - **ईरान:** [चाबहार बंदरगाह](#) परयोजना को **100 करोड़ रुपए** मलिना जारी है, जो पछिले तीन वर्षों से अपरवितरति है ।
 - **अफ्रीका:** अफ्रीकी देशों को सामूहिक रूप से **200 करोड़ रुपए** मलिे, जो इस महाद्वीप के साथ भारत के बढ़ते प्रभाव और जुड़ाव को दर्शाता है ।
- **सेशेल्स:** इसे **10 करोड़ रुपए** से बढ़ाकर **40 करोड़ रुपए** मलिे ।

पड़ोसी देशों को दी जाने वाली वकिस सहायता के क्या लाभ हैं?

- **राजनयिक संबंधों को मज़बूत बनाना:** पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करके, भारत राजनयिक संबंधों को बढ़ाता है, मज़बूत राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है ।
- **क्षेत्रीय स्थरिता को बढ़ावा देना:** वतिलीय सहायता पड़ोसी देशों को स्थरि करने में मदद करती है, जसिसे एक अधिक सुरकषति और स्थरि क्षेत्र बन सकता है, जसिसे भारत के रणनीतिक हतियों को लाभ होगा ।
- **आर्थिक वकिस का समर्थन करना:** सहायता **बुनयिादी ढाँचा परयोजनाओं**, वकिस कार्यक्रमों और अन्य पहलों में योगदान देती है जो प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक वकिस को बढ़ावा दे सकती हैं, जसिसे एक अधिक समृद्ध क्षेत्र बन सकता है। **उदाहरण के लयि, ईरान में चाबहार बंदरगाह ।**
- **व्यापार और नविश को प्रोत्साहति करना:** पड़ोसी देशों में बेहतर **बुनयिादी ढाँचे और आर्थिक स्थिति** भारत के लयि व्यापार एवं नविश के अवसरों

- को बढ़ा सकती है, उदाहरण के लिये, भारत व बांग्लादेश के बीच [अगरतला-अखौरा रेलवे परियोजना](#) ।
- **रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाना:** सहायता प्रदान करने से भारत को प्रभाव डालने और गठबंधन बनाने की अनुमति मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पड़ोसी देशों का भारत के साथ **सकारात्मक जुड़ाव हो एवं वे इसके हितों के साथ अधिक नफिदता** से जुड़ें ।
 - उदाहरणार्थ, **डोकलाम मुद्दे पर भूटान** का भारत के प्रति पक्ष लेना ।
 - **मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करना:** सहायता अक्सर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आपदा राहत जैसी तत्काल **मानवीय आवश्यकताओं** को पूरी करती है, जिससे प्राप्तकर्त्ता देशों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है ।
 - उदाहरण के लिये, भारत ने चक्रवात मोचा के दौरान म्याँमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिये **"ऑपरेशन करुणा"** शुरू किया ।
 - **सॉफ्ट पावर को मज़बूत करना:** पड़ोसी देशों के विकास में निवेश करके, भारत एक ज़मिमेदार क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी सॉफ्ट पावर और प्रतिष्ठा को मज़बूत करता है ।
 - उदाहरण के लिये, यह भारत के छोटे पड़ोसियों के बीच **बगि बरदर सडिरोम** को कम करने में मदद करता है ।

भारत की पड़ोस प्रथम नीति

- **नेबरहुड फ़र्सूट नीति** अर्थात् **पड़ोस प्रथम नीति** की अवधारणा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई ।
- भारत की 'पड़ोस प्रथम नीति' उसके **नफिदतम पड़ोसी राष्ट्रों** अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ **संबंधों के प्रबंधन** के प्रति उसके दृष्टिकोण को नरिदषिट करती है ।
- पड़ोस प्रथम नीति, अन्य वषियों के साथ-साथ, पूरे **क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल और जन-जन समन्वयन व संपर्क** बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार एवं वाणजिय को बढ़ाने के उद्देश्य से है ।
- यह नीति हमारे पड़ोस के साथ संबंधों और नीतियों का प्रबंधन करने वाली सरकार की सभी प्रासंगिक शाखाओं के लिये एक **संस्थागत प्राथमिकता** के रूप में वकिसति हुई है ।
- अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने/समन्वय के लिये भारत का दृष्टिकोण **परामर्श, गैर-पारसपरकित्ता** और **ठोस/वास्तविक परिणाम** प्राप्त करने पर केंद्रित होने की वशिषता है । यह दृष्टिकोण संपर्क, बुनियादी ढाँचे, विकास सहयोग, सुरक्षा को बढ़ाने तथा जन-जन समन्वयन को और भी बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है ।

भारत के लिये नेबरहुड फ़र्सूट/पड़ोस प्रथम नीतिक्रियों महत्त्वपूर्ण है?

- **आतंकवाद और अवैध प्रवास:** भारत को अपने नफिदतम पड़ोसियों से **हथियारों और ड्रग्स की तस्करी सहित आतंकवाद एवं अवैध प्रवासन** के खतरों का सामना करना पड़ता है ।
 - बेहतर संबंध **सीमा सुरक्षा अवसंरचना** में सुधार कर सकते हैं और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय/जनांकीकीय परिवर्तनों की नगिरानी कर सकते हैं ।
- **चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध:** चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं, वशिषकर पाकिस्तान से संबद्ध आतंकवाद के कारण ।
 - क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों में शामिल होने से आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया जा सकता है और पड़ोस प्रथम नीति के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक साझा मंच बनाया जा सकता है ।
- **सीमा सुरक्षा अवसंरचना में निवेश:** सीमा सुरक्षा अवसंरचना में कमी है और सीमा क्षेत्रों को स्थिर एवं वकिसति करने की आवश्यकता है ।
 - सीमा पार सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों जैसे बेहतर कनेक्टविटी बुनियादी ढाँचे तथा ऐसे बुनियादी ढाँचे के लिये एक क्षेत्रीय विकास नधिका पता लगाना ।
- **ऋण व्यवस्था (LOC) परियोजनाओं की नगिरानी:** पड़ोसी देशों के लिये भारत की **LOC** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वैश्विक सॉफ्ट लेंडिंग का 50% हसिसा उन्हें दिया जा रहा है ।
 - यह क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाता है, भारतीय फ़र्मों की उपस्थितिका वसितार करता है और प्राप्तकर्त्ता देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाता है ।
- **रक्षा और समुद्री सुरक्षा:** रक्षा सहयोग महत्त्वपूर्ण है, जिसमें वभिन्न पड़ोसी राष्ट्रों के साथ **संयुक्त सैन्य अभ्यास** किये जाते हैं ।
 - यह वसितारति पड़ोस में **मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस** बढ़ाने में मदद करता है ।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास:** पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास पड़ोस प्रथम और **एकट ईसूट पॉलिसी** जैसी नीतियों के लिये महत्त्वपूर्ण है ।
 - म्याँमार और थाईलैंड जैसे देश पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टविटी, आर्थिक विकास तथा सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि **भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** ।
- **पर्यटन को बढ़ावा:** भारत मालदीव और बांग्लादेश के लिये पर्यटकों का एक प्रमुख स्रोत है तथा नेपाली धार्मिक पर्यटन के लिये एक गंतव्य है ।
 - पर्यटन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय संस्कृति और व्यवसायों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे भारतीय सांस्कृतिक उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मलि सकता है ।
- **बहुपक्षीय संगठन:** पड़ोसियों के साथ भारत का जुड़ाव **SAARC** और **BIMSTEC** जैसे क्षेत्रीय तंत्रों द्वारा संचालित होता है ।
 - दोनों भारत को दक्षिण एशिया में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को स्थापित करने और क्षेत्र में अन्य प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं ।

अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सीमा विवाद:** सीमाओं पर मतभेद, वशिष रूप से **चीन और पाकिस्तान के साथ**, तनाव एवं संघर्ष का कारण बनते हैं ।

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव और पाकस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध सामरिक चुनौतियों का कारण हैं।
- आतंकवाद: पाकस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे विभिन्न आतंकवादी समूहों को लगातार समर्थन, सुरक्षा पनाह तथा धन मुहैया कराया है, जिन्होंने भारत में हमले किये हैं।
- अवैध प्रवास: बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासियों के आने से जनसांख्यिकीय और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- व्यापार असंतुलन: पाकस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ आर्थिक मुद्दे एवं व्यापार बाधाएँ संबंधों को प्रभावित करती हैं।
 - व्यापार प्रतर्बिंधों और शुल्कों से संबंधित मुद्दों ने पर्याय: कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।
- जल विवाद: सिंधु और तीस्ता नदियों जैसे नदी जल संधि पर विवाद क्रमशः पाकस्तान तथा बांग्लादेश के साथ संबंधों को खराब करने का कारण रहे हैं।
- आंतरिक संघर्ष: नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता या विवाद द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हैं।
- राजनयिक संबंध: श्रीलंका में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और म्यांमार सरकार पर भारत के रुख जैसे मुद्दे तनाव उत्पन्न करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) का मुद्दा।
- पर्यावरण संबंधी मुद्दे: प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय समस्याओं (जैसे- बांग्लादेश में बाढ़) के लिये संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है जिससे संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
 - उदाहरण के लिये, भूटान की BBIN और पर्यटन के कारण उसकी नाजुक पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएँ।
- क्षेत्रीय सहयोग: SAARC और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय संगठनों के भीतर मतभेद प्रभावी सहयोग में बाधा डाल सकते हैं।

पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिये भारत की पहल

- नेबरहुड फरसट नीति
- एकट ईसट पॉलिसी
- 'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर)
- प्रोजेक्ट मौसम
- बमिस्टेक
- सारक का कार्याकल्प
- गुजराल सदिधांत

आगे की राह

- राजनयिक जुड़ाव को मज़बूत करना: मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिये नियमित राजनयिक संवाद तथा उच्च स्तरीय बैठकें स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना।
 - विवादों को सुलझाने के लिये संयुक्त समितियों और मध्यस्थता पैनलों जैसे तंत्रों का विकास तथा संस्थागतकरण करना।
- आर्थिक सहयोग बढ़ाना: नष्टिपक्ष व्यापार समझौतों पर वार्ता करना और उन्हें लागू करना जो असंतुलनों को दूर करें तथा पारस्परिक लाभ को बढ़ावा दें।
 - कनेक्टविटी और आर्थिक एकीकरण में सुधार के लिये सड़क, रेलवे तथा ऊर्जा गलियारों पर सहयोग करना।
- सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना: आतंकवाद तथा अवैध प्रवास जैसे आम खतरों से निपटने के लिये क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों पर समन्वय करना।
 - संयुक्त कार्य बल और खुफिया-साझाकरण तंत्र स्थापित करना।
- लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना: लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना बनाने के लिये शैक्षिक तथा पर्यटन पहलों को बढ़ाना।
- पर्यावरण और मानवीय मुद्दों को संबोधित करना: संयुक्त प्रयासों तथा क्षेत्रीय योजनाओं का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरणीय समस्याओं को समन्वित करना। संकट के समय में मानवीय सहायता व समर्थन प्रदान करना, सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देना।
- संयुक्त प्रयासों और क्षेत्रीय योजनाओं का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं तथा पर्यावरणीय समस्याओं पर तालमेल बैठाना।
- क्षेत्रीय संगठनों को मज़बूत बनाना: क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान तथा नरिणय लेने और कार्यान्वयन के लिये उनके तंत्र में सुधार करने हेतु सारक एवं बमिस्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- आंतरिक और बाह्य कारकों पर ध्यान देना: सुनिश्चित करना कि घरेलू नीतियों का पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
 - ऐसी संतुलित नीतियों के लिये प्रयास करना जो गुजराल सदिधांत के अनुरूप घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों के प्रभावों पर विचार करें।

दृष्टिभेनस प्रश्न:

प्रश्न: बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत के पड़ोस में स्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है? चर्चा कीजिये।

अधिक पढ़ें: [वदिश मंत्रालय की विकास सहायता](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. उन परिस्थितियों की समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में नरिणायक भूमिका का नरिवहन करना पड़ा। (2013)

प्रश्न. परियोजना 'मौसम' को भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परियोजना का एक रणनीतिक आयाम है? चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. गुजराल सदिधांत का क्या अभिप्राय है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिये। (2013)

प्रश्न. "बहु-धार्मिक और बहु-जातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में देख रहे अतविवाद के संघात के प्रतिनिधिपद नहीं है।" ऐसे वातावरण के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/neighbourhood-first-in-mea-s-aid-allocation>

